>

Title : Need to have junk disposal norms in the country in order to control the incidents like detection of Cobalt-60 in Delhi.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Thank you for allowing me to raise the important matter. The recent incident in Mayapuri Industrial Area of Delhi where more than five persons have suffered high radiation doses due to accidental exposure to highly radioactive Cobalt-60 should be seen as a wake up call for tightening security and accountability in respect of radioactive materials. Almost all developed countries have devised mechanism to keep a check on the dispersal of radioactive materials in public places. But our country has so far devised no formal mechanism that would detect the presence of a nuclear substance in a public area and has prepared no roadmap as to how to deal with it in case of any emergency. All this is despite the fact that India is on the list of terrorist groups. They are planning to use third generation terror weapon which is called Radiological Dispersal Devices (RDD), that are also called `dirty bombs'. I am told that a Core Group prepared guidelines and submitted to the Government but why those guidelines are yet to see the light of the day! Many questions need to be resolved in this case. Had any radioactive material included in the scrap already been disposed of since early March? What was the origin of the scrap? Was it domestic or imported? All scraps acquired over the past months need to be traced back and investigated to find out who was responsible for the disposal of Cobalt-60 containing scrap?

Was any contaminated scrap sold and processed into steel products? Has any quantity of Cobalt-60 spilled out of its container and got dispersed? The case is complicated and needs a combination of determined police work and technical expertise to resolve the host of issues involved. If this Cobalt-60 was imported with scrap, how did it pass through the customs? The Government should explain. It raises questions about the trade in such materials and how their movement escapes detection. I fear India is being treated as a dumping yard for such dangerous wastes. There is an urgent need to have junk disposal norm in the country.

MADAM SPEAKER: Thank you. Shri Shahnawaz Hussain, Veerender Kashyap,

Shri M.B. Rajesh and

Shri P.D. Rai will associate with this. आप अपने को एसोसिएट करें। हमें और भी सदस्यों को अपनी बात कहने का समय देना है।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): हम लोग जब भी बोलने के लिए खड़े होते हैं तो हमारे लिए एक लाइन कहना भी मुश्किल हो जाता है।

अध्यक्ष महोदया: ऐसी बात नहीं है, आपने तो नोटिस भी नहीं दिया था।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैंने इसीलिए आपसे दरख्वास्त की थी, आपसे गुजारिश की थी कि मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, लेकिन यह कहना सही नहीं है कि एक लाइन बोलना भी मुश्किल हो जाता है।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अध्यक्ष महोदया, देश की राजधानी दिल्ली में आसमान में आग है, हवा में प्रदूषण है और पानी जहर है। जिस शहर में हम लोग रह रहे हैं, उसमें कचरे का रेडिएशन है। जिस तरह से माननीय सदस्य ने अभी इस विषय को उठाया है, यह कोबाल्ट-60 से पूरा देश चिंतित है। कुछ समय बाद यहां कॉमनवैल्थ गेम्स होने वाले हैं। इस रेडिएशन से पूरे देश की बदनामी हो रही है। सरकार कह रही थी कि हम न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल लाना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पर एतराज किया है। हम कहना चाहते हैं कि हमने इसलिए एतराज किया था कि यह वेकअप अलार्म है कि अगर एक कोबाल्ट-60 से इतने लोग बीमार हो सकते हैं, तो सरकार जब न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल लाएगी, तो उससे और कितनी दुश्वारी हो सकती है, यह समझा जा सकता है। आज दिल्ली का विषय संसद में नहीं उठ पाता है, क्योंकि दिल्ली से कांग्रेस के सांसद जीतकर आए हैं और उन्हें इस विषय को उठाने की फुर्सत नहीं है। आज दिल्ली के लोग जहरीला पानी पीने से बीमार हो रहे हैं, कई बच्चे भी मर गए हैं, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। कोबाल्ट-60 के कारण कई लोग बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन इस दिल्ली में इस बात की कोई चर्चा नहीं हो रही है। मैडम, दिल्ली में न तो बिजली है, न पानी है। आप यह देखें कि आज संसद में भी 15 बार बिजली कटी है। अगर दिल्ली में इतनी गर्मी में बिजली कट रही है, जहरीला पानी पीने को लोग मजबूर हैं, हवा में प्रदूषण है, कचरे में कोबाल्ट-60 आ रहा है, तो समझिए कि जब देश की राजधानी का यह हाल है तो अन्य जगहों का क्या हाल होगा।

अध्यक्ष महोदया: अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि सरकार तुंत इस पर रिस्पॉंड करे और दिल्ली के सोए हुए सांसद जाग कर अपने शहर की समस्या को यहां उठाएं।

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): अध्यक्ष महोदया, दिल्ली में मायापुरी स्क्रैप मार्केट में एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार स्क्रैप से कोबॉल्ट-60 से लैस रेडियोएक्टिव मैटिरियल मिलने से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। बड़ा सवाल स्क्रैप की जांच प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। मायापुरी में विदेशों से भी स्क्रैप मैटिरियल आता है। आमतौर पर विदेशों से आने वाला सामान जांच के बाद ही मार्केट में आता है, लेकिन अब कोबॉल्ट-60 से लैस स्क्रैप मैटिरियल के मार्केट में पहुंचने के बाद इनकी जांच प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले की जांच से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि विदेश से आने वाले माल की जांच करने वालों रेडियोएक्टिव मैटिरियल का पता लगाने

के लिए अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। उनके पास रेडियोएक्टिव मैटिरियल का पता लगाने वाले आधुनिक उपकरण भी मौजूद हैं। इसके बावजूद अगर इस तरह का मैटिरियल मार्केट में आया है, तो यह गंभीर मामला है। सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। यदि एंट्री पाइंट पर ही मुस्तैदी बढ़ा दी जाएऔर इस तरह के घातक मैटिरियल की वहीं पर पहचान कर ली जाए, तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। विदेशों से आने वाले मान के कंटेनर जहां उतरते हैं, उनमें रखे सामान की वहीं पर कड़ी चेकिंग की जानी चाहिए, ताकि ऐसा माल बाजार तक न पहुंचे।

कोबाल्ट-60 को लेकर हर स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है। बात चाहे अस्पताल में रेडिएशन

सेफ्टी की हो या दूसरी जगहों पर रेडियोएक्टिव तत्वों की जांच की, प्रशासन की ढील से नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि मायापुरी जैसे हादसे कभी भी, कहीं भी हो सकते हैं। हालत यह है कि यहां के ज्यादातर बड़े अस्पतालों में रेडिएशन सेफ्टी के लिए कोई सिस्टम नहीं है। अस्पतालों का रेडिएशन फ्री रखने की जिम्मेदारी अनट्रेंड वर्कर्स पर है, क्योंकि यहां रेडिएशन सेफ्टी

अफसर नहीं हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रेडिएशन वाली चीजों के मामले में सरकारी स्तर पर काफी लापरवाही हो रही है। कड़े नियमों के अभाव में संक्रमित रेडियोएक्टिव चीजों का बाजार देश में तेजी से बढ़ रहा है। स्क्रैप न्यूज रीसाइकलिंग जर्नल के आंकड़ों के मुताबिक, केवल यूरोपीय देशों से ही भारत को इससे 23 ट्रिलियन रुपए का कारोबार मिल रहा है। गैर सरकारी संस्था, टॉक्सिस वाच के विशेषज्ञ कहते हैं कि स्क्रैप की रीसाइकलिंग से बनी चीजों में रेडिएशन की जांच को लेकर बरती जा रही लापरवाही से आर्थिक

---

* Speech was laid on the Table.

व स्वास्थ्य को नुकसान तो हो ही रहा है, देश की छवि भी खराब हो रही है। इसी के चलते पिछले साल भारत से स्टील प्रोडक्ट के 123 शिपमेंट यूरोपीय देशों में भेजे गए थे, लेकिन करीब 50 प्रतिशत शिपमेंट कई यूरोपीय देशों ने लेने से इन्कार कर दिया। उन्होंने बताया कि जो भी शिपमेंट वापस लौटे, वे सभी रेडियोएक्टिव तत्वों से संक्रमित पाए गए थे।

ऐसी गम्भीर स्थिति को देखते हुए मैं भारत सरकार के संबंधित मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में तत्काल सतर्कता बरती जाए और सरकारी स्तर पर व्याप्त लापरवाही को तुंत दूर किया जाए और चुस्ती लाई जाए, ताकि देश के अंदर और देश के बाहर हम अपनी छवि को सुधार सकें और इस खतरे से देश को मुक्त कर सकें।

अध्यक्ष महोदया: श्री धर्मेन्द्र यादव, कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।